Publication	The Pioneer	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	PTI
Date	17/01/2023	Page no	10

NDDB, Amul, NAFED to be among promoters of national cooperative society for organic products

PTI ■ NEW DELHI

National Dairy Development Board (NDDB), Amul and NAFED will be among the five promoters of the newly announced national-level cooperative society for organic food products, which will focus on enhancing farmers' income by improving production, certification and marketing system.

Last week, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved a proposal to establish three new national-level multi-state cooperative societies to promote organic products, seeds and exports.

A national-level cooperative organic society, a cooperative seed society and a cooperative export society will be registered under the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002.

According to sources, the National Cooperative Organic

Society, to be based in Anand, Gujarat, will be set up with an authorised share capital of Rs 500 crore. It will have an initial paid-up share capital of Rs 100 crore, sources said.

NDDB, co-operative NAFED, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (GCMMF), which markets milk products under the Amul brand, National Cooperative Development Corporation (NCDC) and National Cooperative Consumers' Federation of India Ltd (NCCF) have come forward to become promoters of this new society and they will contribute Rs 20 crore each for initial paid-up share capital, sources said.

The NDDB will be the main promoter, they said, adding that these products would be marketed under the Amul brand. A new brand will also be unveiled for the marketing of the products globally.

Initially, the focus of this national-level society would be on improving the marketing system so that farmers get a better income for their organic produce. Gradually, the certification system and testing labs will also be strengthened.

"There are 8.54 lakh registered cooperatives in the country with more than 29 crore members. Cooperatives can be utilised for the development of organic clusters and its entire supply chain," a source said.

On the potential, sources said that India accounts for only 2.7 per cent of the world organic market and thus has a huge potential to expand.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Business Standard	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	PTI
Date	17/01/2023	Page no	4

National Cooperative Society to have ₹500-cr share capital

National Dairy Development Board (NDDB), Amul and NAFED will be among the five promoters of the newly announced national-level cooperative society for organic food products, which will focus on enhancing farmers' income by improving production, certification and marketing system. According to sources, the National Cooperative Organic Society, to be based in Anand, Gujarat, will be set up with an authorised share capital of ₹500 crore. It will have an initial paid-up share capital of ₹100 crore, sources said. **PTI**

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Amar Ujala	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	17/01/2023	Page no	9

अब सहकारी समितियों के जरिये जैविक कृषि उत्पादों का प्रचार करेगी सरकार

नई दिल्ली। जैविक कृषि उत्पादों को किसान यदि अपने स्तर से बेचने का प्रयास करें तो उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं होता है इसलिए सरकार का मानना है कि सहकारी समितियों के जरिये इन्हें बेचना ज्यादा फायदेमंद होगा।

केंद्रीय कृषि सचिव गणेश कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जैविक कृषि उत्पादों को बेचने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कोऑपरेटिव समिति के गठन को मंजूरी दी है। इसमें अलग-अलग मंत्रालयों का सहयोग होगा। कुमार ने बताया, हमारे पास बाजार है, हमारे पास ग्राहकों की मांग है और यदि

कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर के कोऑपरेटिव समिति के गठन को दी मंजूरी

आप सीधे किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह बातें इस विषय से संबंधित हितधारकों के साथ बैठक में कही।

उन्होंने सामान्य और जैविक गेहूं के दाम में अंतर का जिक्र करते हुए कहा, यह अंतर 20 से 25 रुपये प्रति किलो का है। ऐसे में किसानों को अतिरिक्त कमाई करवाने में सहकारिता की खास भूमिका सामने आती है। सरकार ने जिस राष्ट्रीय समिति के गठन को मंजूरी दी है वह जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी।

इसमें जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण, भारत और विदेश में मांग और खपत की क्षमता को बढ़ाना, ब्रांडिंग आदि शामिल हैं। इस सहकारी समिति का नाम नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लि. होगा और इसके 5 प्रवर्तक होंगे। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (अमूल), नैफेड, एनसीसीएफ, एनडीडीबी और एनसीडीसी मिलकर इस जैविक सहकारी समिति को आरंभ करेंगे। ब्यूरो

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Hindustan	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	17/01/2023	Page no	11

जैविक सहकारी समिति वैश्विक बाजार में नई पहचान बनाएगी

पहल

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार 'सहकार से समृद्धि' के मूल मंत्र के तहत जैविक खेती को विश्व जैविक बाजार में नई पहचान बनाने की दिशा में काम कर रही है। इससे उन लाखों किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी जो जैविक खेती के सहकारी-नेतृत्व वाले आंदोलन में शामिल होंगे। इसके लिए पांच प्रमुख समितियां आगे आई हैं, जो एक जैविक सहकारी समिति का गठन करेगी।

सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देश के जैविक खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सहकारी समितियां सामने आई हैं।

इसमें गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और अन्य दो राष्ट्रीय स्तर के संगठन- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक जैविक सहकारी समिति स्थापना करेगी। इस समिति के पास 500 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी होगी और इसकी प्रारंभिक चुकता शेयर पूंजी 100 करोड़ होगी।

किसानों को कम लागत में सुविधा उपलब्ध होगी

यह समिति एकत्रीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, रसद सुविधाओं, जैविक उत्पादों के विपणन के लिए के रूप में कार्य करेगी। इससे देश में जैविक प्रमाणन और मानकीकरण के लिए आवश्यक परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने में मदद करेगी। किसानों को कम लागत पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। ब्रांड विकास और मानकीकरण से उपभोक्ता का विश्वास बढ़ेगा और बिक्री में सुधार होगा, जिससे जैविक किसान सदस्यों की आय में वृद्धि होगी। देश में 8 .54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिनमें 29 करोड़ से अधिक सदस्य हैं।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Rashtriya Sahara	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	17/01/2023	Page no	7

सहकारिता मंत्रालय जैविक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराएगा

नई दिल्ली (एसएनबी)। सरकार एक तरफ जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहती है वहीं दूसरी तरफ भारत के जैविक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बाजार भी उपलब्ध कराना चाहती है। दरअसल सहकारिता मंत्रालय का भी अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर आने वाले दिनों में जैविक उत्पाद के बाजार का आकार दस लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। सरकार को लगता है कि कृषि उत्पादों की बिक्री के काम को सहकारी समितियां अधिक कुशलता से कर सकती है और इससे किसान को अच्छा दाम भी मिल सकता है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए हाल में सरकार ने बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत जैविक उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति की स्थापना को मंजूरी दी थी।

दरअसल सरकार का मानना है कि सहकारी समिति वैश्विक स्तर पर बाजार के अनुरूप सोच सकती है और भारत की कई सहकारी समितियां ऐसा कर भी रही है। दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, खपत के मामले में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और चीन शीर्ष उपभोक्ताओं में से है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार 190 देशों में 34 लाख जैविक उत्पादक है।

****

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD